International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 31-01-2023, Accepted: 15-02-2023, Published: 04-03-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 41-45

मोदी कार्यकाल मे भारत की चीन के प्रति विदेश नीति

डॉ. अखिलेश त्रिपाठी[1], हितेश कुमार गुप्ता[2]
[1] सहायक आचार्य, राजनितिक विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी.कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोधार्थी, राजनितिक विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
इस शोध लेख का मुख्य उद्देश्य मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की विदेश नीति में चीन के संदर्भ में जो बदलाव आए हैं उनका विश्लेषण और व्याख्या करना है यह शोध लेख मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है पहला भाग मोदी की विदेश नीति की विशेषताओं की व्याख्या करता है साथ ही दूसरा भाग शी जिनपिंग सत्ता में आने के बाद हुए विदेश नीति में बदलाव का विश्लेषण और विशेषताओं की व्याख्या करता है तीसरा भाग वर्तमान समय में चीन को लेकर भारतीय विदेश नीति के सम्मुख चुनौतियों की व्याख्या करता है वही चौथा भाग भारत द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई जा रही रणनीतियों की व्याख्या करता है पांचवां व अंतिम भाग विभिन्न आयामों से मोदी की चीन के प्रति विदेश नीति की व्याख्या करता है।

मूल शब्द: सलामी सालसिंग (Salami slicing) रणनीति, रेशम मार्ग (BRI), QUAD, वुल्फ वोर्रीयर डिप्लोमेसी, मध्य साम्राज्य, पुनः सयोजनवादी (Irredentist Power), कर्ज जाल (Debt trap), मोतियों की माला

शी जिनपिंग 2013 में चीन की सत्ता में आते हैं साथ ही नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होते हैं शी जिनपिंग को आधुनिक माओ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी नीतियों और संविधान में इतना बदलाव कर दिया है की चीन में उनसे शक्तिशाली नेता और कोई भी नहीं है और ना ही उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी है इसके लिए शी जिनपिंग ने सबसे पहले संविधान में बदलाव करते हुए अपने को हमेशा के लिए चीन का राष्ट्रपति बना दिया या कहे कि चीन का सर्व सत्तावादी नेता बना दिया है शी जिनपिंग माओ की तरह ही मध्य साम्राज्य (Middle kingdom) और चाइनीस स्वप्न (Chinese Dream) को लेकर चलते हैं और अपनी हर नीति निर्माण करते वक्त इन दोनों का ध्यान रखते हैं इसी कारण चीन आज एक पुनः संयोजन वादी (irredentist Power) के रूप में सामने आ रहा है पुणे संयोजन वादी राष्ट्र वह होता है जो जो आधुनिक समय में उस क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो प्राचीन काल में कभी वर्षों पहले उसका हुआ करता था इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस क्षेत्र पर चीन दावा करता है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र भारत की संप्रभुता वाले क्षेत्र में भी आता है इसके लिए इसके लिए पहले माओ ने हथेली और पांच उंगलियां (Palm And Five Finger Policy) की नीति अपनाई थी उसी नीति का का पालन वर्तमान चीन सरकार द्वारा भी किया जा रहा है वही साथी वर्तमान भारतीय सरकार जिसकी पहचान एक कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में होती है जिसने अपनी सत्ता राष्ट्रवाद के प्रचार और कांग्रेस विरोध के प्रचार के द्वारा प्राप्त की वर्तमान कांग्रेस की नीतियों की घोर विरोधी है क्योंकि वर्तमान सरकार का मानना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जो चीन की विदेश नीति को समझने में बड़ी भूल कर बैठे थे जिसका खामियाजा भारत ने अपने भूमि के 38,000 sq km क्षेत्र गवा कर भुगतना पड़ा इसलिए यह सरकार कांग्रेस की नीतियों को पलट देना चाहती है साथ ही वर्तमान सरकार समय–समय पर अखंड भारत की ही बात करती है जो उनकी हर नीति का मुख्य आधार रहता है और उनके राष्ट्रवाद का भी प्रमुख आधार है या फिर स्पष्ट कहें कि यह वर्तमान सरकार का स्वप्न भी है आज इसी कारण जब भी दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की बात होती है तो दोनों देशों का कट्टर राष्ट्रवाद या कहें कि दोनों देशों का चीनी स्वप्न बनाम अखंड भारत आमने सामने होता है इसी कारण आज दोनों देशों के आर्थिक संबंध तो मजबूत ही हैं जैसे 2022 मे दोनों देशों के बीच का व्यापार 135 USD पहुंच गया है सांस्कृतिक संबंध भी बेहतर ही हैं मगर राजनीतिक संबंध हमेशा की तरह उतार–चढ़ाव से पूर्ण हैं जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उनके सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि चीन का किस प्रकार मुकाबला किया जाए क्योंकि चीन एक ऐसा राष्ट्र है जिसे प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन भी घोषित नहीं किया जा सकता और ना ही भारत उस पर शत–प्रतिशत विश्वास ही कर सकता है इसलिए भारत की वर्तमान सरकार ने मुद्दे आधारित विदेश नीति का पालन कर रही है जिसका जिक्र 2019 के रायसीना डायलॉग में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले द्वारा किया गया था जिसका अर्थ होता है कि किसी भी देश के साथ पूर्ण तरह संबंध विच्छेद ना करना और राष्ट्र हित को आधार बनाकर किसी भी मुद्दे का समर्थन और विरोध करना जैसे भारत द्वारा चीन की परवाह न करते हुए क्वाड (Quad) में शामिल होना साथ ही अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए चीन के वन बेल्ट वन रोड इनीशिएटिव का समर्थक ना बनना और RCEP (Regional Comprehensive Economic partnership) में अपने राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल ना होना मगर वर्तमान चीनी सरकार भारत के सामने बहुत ही चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है जैसे उसकी सबसे महत्वकांक्षी नीति BRI (BELT And ROAD INITIATIVE) जिसके माध्यम से वह भारत के पीओके वाले क्षेत्र में निवेश कर रहा है या फिर सीमा विवाद के कारण दोनों देशों की सेनाएं 2017 में डोकलाम में 2020 में बलवान में और 2022 में तवांग वाले क्षेत्र में आमने–सामने हो चुकी हैं साथ ही चीन की मोतियों की माला की नीति (String of Pearls) के तहत भारत को 360 डिग्री घेरना चाहता है साथी ही अपनी कर्ज जाल (Debt trap) की नीति के तहत वह भारत के पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप भारत के पड़ोसी उससे दूर जा रहे हैं साथ ही भारत भी इसके प्रतिरोध स्वरुप बहुत सी रणनीतियां बना रहा है जैसे भारत द्वारा चीन की मोतियों की माला की नीति के विरोध में नेकलेस ऑफ डायमंड (Necklace of Diamond) की नीति का अनौपचारिक रूप से

पालन कर रहा है साथ ही चीन की कर्ज जाल की नीति का मुकाबला करने हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट किस सुविधा द्वारा पड़ोसी देशों को अपने विश्वास में लाने का प्रयास कर रहा है साथ ही सीमा पर भारत अपनी आधारभूत संरचना का मन को मजबूत कर रहा है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दौलत बेग ओल्डी रोड है इन प्रयासों के माध्यम से वर्तमान मोदी सरकार शी जिनपिंग की आक्रामक और विस्तार वादी नीति का सामना करने का प्रयास कर रही है और भारत के सम्मुख उनका विस्तारपूर्वक विश्लेषण लेख में आगे किया गया है

मोदी की विदेश नीति की विशेषता

मोदी अपनी चुनाव प्रसार मैं कांग्रेस की नीति का जमकर विरोध करते हैं उनके अनुसार वर्तमान में भारत की विदेश नीति के सम्मुख सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस की गलत नीतियां ही थी इससे इतना तो स्पष्ट था कि मोदी कांग्रेस की नीतियों में समूल परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करने का प्रयास काफी हद तक क्या भी उनके व्यक्तित्व और चुनाव में मिली अपार सफलता के कारण वह कुछ बड़े फैसले लेने की क्षमता रखते थे और ऐसी सरकार भारत में काफी लंबे समय के बाद बनी थी इसी कारण थी राजा मोहन ने मोदी के आगमन को थर्ड रिपब्लिक (THIRD REPUBLIC) की संज्ञा दी और मोदी की विदेश नीति कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं

प्रथम – विदेश नीति राष्ट्रहित की सिद्धि का साधन आज भारत अपने राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे रहा है भारत अपने विरोधी राष्ट्र चाहे वह चीन ही क्यों ना हो की परवाह किए बगैर विदेश नीति का निर्माण कर रहा है जैसे भारत द्वारा क्वाड में शामिल होना और उसमें सक्रिय भूमिका निभाना बगैर चीन की परवाह किए द्य साथी ही भारत द्वारा आर. सी. ई. पी.(क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार भागीदारी)की सदस्यता ना स्वीकार करना जिसका सबसे बड़ा कारण चीन ही था भारत द्वारा रूस से s400 मंगवाना बिना अमेरिका की परवाह किए भारत द्वारा चीन की बी आर आई नीति में शामिल ना होना इन सब का कारण भारत द्वारा राष्ट्र हित को प्राथमिकता देना था हाल ही में जनवरी 2023 में भारत ने अग्नि–5 नामक मिसाइल का परीक्षण किया उसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है जबकि भारत एमटीसीआर का हस्ताक्षर करता देश है साथ ही चीन द्वारा भी इसका विरोध किया गया और यूएन में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास चीन ने किया मगर भारत ने किसी की परवाह किए बगैर यह परीक्षण किए कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान पर उरी और पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक की इन सब का कारण भारत द्वारा राष्ट्र हित को प्राथमिकता को सर्वोपरि माना बगैर अपने दुश्मन राष्ट्र की चिंता किए

द्वितीय – प्रभावकारी बहुपक्षवाद रू आज भारत उन देशों के साथ भी संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रहा है जिसकी अनदेखी पहले भारत करता था और विश्व समुदाय जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता जैसे मोदी द्वारा 2015 में मंगोलिया जाने वाले पहले पीएम बने 2015 में वियतनाम को अपना सैन्य बल मजबूत करने हेतु 500 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ़ क्रेडिट दिया 2021 में भारत द्वारा फिलिपींस और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता हुआ इन देशों का उद्देश्यचीन से रक्षा करना था क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में और साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है इन सब का फायदा उठाकर भारत इन देशों से अच्छी मित्रता कर रहा है

तृतीय – विदेश नीति को राष्ट्रीय आर्थिक हित से जोड़ना भारत द्वारा एफडीआई को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ आज भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं चला रहा है ताकि राष्ट्र उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके इसी का नतीजा है कि भारत रक्षात्मक उपकरण का निर्यात 2020–21 में 12815 करोड़ रुपए पहुंच गया (Raksha-Anirveda.Com) जो 2014–15 में 1940 करोड़ था (pib.gov.in) साथ ही 2021 में भारत द्वारा आरसीइपी (रीजनल इकोनामिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप) की सदस्यता स्वीकार नहीं करना जिसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा अपने घरेलू छोटे उद्योगों डेयरी उत्पादों कृषि उत्पादों की रक्षा करना था

चतुर्थ – भारतीय सेना द्वारा बीते कुछ वर्षों में विरोधी राष्ट्र को कड़ा जवाब देने के लिए कड़ा सैन्य प्रतिरोध की नीति अपना रही है इसका उदाहरण 2016 के बालाकोट स्ट्राइक हो जा फिर 2019 का पठानकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो इसके साथ ही चीन को भी समय–समय पर भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया है चाहे वह 2017 का डोकलाम– 2020 का गलवान संकट हो या फिर 2022 की तवांग मे होई झड़पे की क्यों ना हो !

पंचम – भारतीय प्रवासी और विदेश नीति रू भारत की विदेश नीति में प्रवासी भारतीय लोग बड़ी महत्व भूमिका निभा रहे हैं यह विदेशों में भारत के लिए पक्षजुटाव या लॉबिंग का काम करते हैं और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं और भारत की छवि को विदेश में अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का कार्य भी करते हैं यह भारत द्वारा विदेशों में निवेश और विदेशी द्वारा भारत में निवेश को प्रोत्साहन करता है भारतीय प्रवासियों के कारण ही 2019 में हावडी मोदी 2019 में ही कनाडा में तिरंगा यात्रा और प्रत्येक वर्ष निवासी होने वाली तिरंगा यात्रा इन सब ने विदेशी संबंधों को प्रभावित किया है और भारत और विदेशी देशों के संबंध मजबूत हुए हैं

चीन की विदेश नीति की विशेषता

शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद उन्होंने विदेश नीति में बहुत से बदलाव किए हैं सबसे पहले 2018 में अपने कार्यकाल को असीमित समय के लिए कर दिया साथ ही उन्होंने अपनी सत्ता की वैधता को बनाए रखने हेतु कट्टर राष्ट्रवाद का सहारा लिया और सी जिनपिंग ने माओ की भांति अपनी जनता को चाइनीस स्वप्न और चीन को महाशक्ति बनाने का सपना दिखाया जिसके लिए शी जिनपिंग ने अपने गौरवपूर्ण इतिहास का सहारा ले रहे हैं जिसमें मध्य साम्राज्य रेशम मार्ग जिसने प्राचीन काल में चीन की सभ्यता को महान बनाने का कार्य किया था को वर्तमान संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए चीन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव माओ की हथेली और पांच उंगली (Palm and five finger policy) की नीति का पालन कर रहे हैं सत्ता में आते ही देश की विदेश नीति को इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम बना रहे हैं वर्तमान चीन की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं जैसे

प्रथम – वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शी जिनपिंग ने सत्ता में आते ही डंग सिओपिंग (Deng Xiaoping) की कीप आ लो प्रोफाइल जिसके तहत चीन को अंदर ही अंदर विकास करना था उसका प्रचार प्रसार करना चीन को महाशक्ति बनाना ऐसा चीन का उद्देश्य नहीं था मगर सी जिनपिंग के आते ही चीन ने वुल्फ वॉरियर की नीति को अपनाया जिसके तहत चीन सरकार अपनी विचारधारा का विस्तार करती है यह बातचीत की अधिक आक्रामक और टकराव वाली शैली है जिसके लिए एक शब्द है जिसका प्रयोग 2015 में चीनी फिल्म वुल्फ वॉरियर जो राष्ट्रवादी और चीनी लड़ाकू पर केंद्रित थी तब से चीनी सरकार की नीतियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में चीन भारत–ऑस्ट्रेलिया यूएसए के खिलाफ इसी नीति का अपना रही है जिसके तहत चीनी सरकार जिनको वह अपना विरोधी मानती है उनके प्रति कड़ा रवैया अपनाते हैं

द्वितीय – पुनः सयोजनवादी (Irredentist) चीन की वर्तमान सरकार पुणे संयोजन वादी की नीति का पालन कर रही है जिसके तहत कोई भी देश ऐतिहासिक और संस्कृति के आधार

पर किसी दूसरे के क्षेत्र पर दावा करता है या उस क्षेत्र पर आक्रमण द्वारा कब्जा करने का प्रयास करता है वर्तमान में चीन द्वारा हथेली और 5 फिंगर की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है चीन का मानना है कि हान राजवंश के समय क्षेत्र जिस पर उसका नियंत्रण था चीन आज दावा करता है की वह क्षेत्र चीन से संबंधित है चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे प्राप्त करना चाहता है !

तृतीय– मध्य साम्राज्य (Middle kingdom): प्राचीन काल से चीन की स्वयं निर्मित धारणा है वह मानता है कि कि चीन विश्व के मध्य में स्थित है और उसकी सभ्यता सबसे महान सभ्यता है जिस पर सभी सभ्यताओं को गर्व करना चाहिए और विश्व को चीन का पालन करना चाहिए ना कि चीन को विश्व का पालन करना चाहिए इसी नीति के तहत चीन वर्तमान समय में विश्व की नंबर वन महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए चीन ने 2035 में सोशलिस्ट मॉर्डनाइजेशन का लक्ष्य रखा है और 2050 तक चीन ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनने का लक्ष्य रखे हुए हैं चीन का लक्ष्य यूएसए को पीछे कर नंबर वन महाशक्ति बनाना है आज चीन वैश्विक उत्पादन का केंद्र बन चुका है उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और सैन्य बल में भी चीन द्वितीय स्थान पर है

चतुर्थ –केन्द्रीयकृत और व्यक्तिगत विदेश नीति :– शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद केंद्रीय करण पर जोर दिया है उसने केंद्र और प्रांतीय स्तर पर जो निर्णय निर्माण को प्रभावित करते थे उनको हटा विदेश नीति के निर्णय को केंद्रित कर दिया है साथ ही पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने हेतु NGOs पर लगाम लगाई साथ ही शी जिनपिंग ने गैंग ऑफ फोर जो चीन में निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उनको हटा दिया साथ ही चीन द्वारा हांगकांग के लोकतांत्रिक आंदोलन को भी शक्ति से दबाया गया पश्चिमी उदारवादी मूल्य को सीमित करने का प्रयास सी जिनपिंग द्वारा लगातार किया जा रहा है वह यह सब चीन में सेंचुरी ऑफ रिलेशन वह राष्ट्रवाद की आड़ में कर रहे हैं ऐसा माना जाता है माओ को साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्ति के प्रतीक तो देंग सिओपिंग को आर्थिक मजबूती का प्रतीक तो सी जिनपिंग चीन को महाशक्ति बनाने के का प्रयास कर रहे हैं ये यह मानते हैं कि जिस प्रकार बीसवीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व माओ ने किया उसी प्रकार 21वीं शताब्दी का प्रत्येक तो शी जिनपिंग द्वारा किया जाएगा

वर्तमान मे चीन द्वारा भारत को दी जा रही चुनौतियां

वैसे तो चीन भारत के सम्मुख स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चुनौती या प्रस्तुत कर रहा है और भारतीय विदेश नीति के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक प्रधानमंत्री के सामने यही रहती है कि चीन का सामना किस प्रकार किया जाए इसी कारण एक समय भारत के पूर्व रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को दुश्मन नंबर वन तक कह दिया था इसलिए मोदी के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि शी जिनपिंग के सत्ता में आने उनकके महाशक्ति बनने के स्वप्न की राह में सबसे बड़ी बाधा भारत ही है क्योंकि चीन को भारत द्वारा ही एशिया में चुनौती दी जा सकती है इसलिए चीन भारत को अलग करने का प्रयास कर रहा है चीन द्वारा भारत के सम्मुख चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं

प्रथम – चीन की बी.आर.आई. परियोजना चीन के प्राचीन राजवंश चौहान राजवंश 206 BC से 220 AD के दौरान सिल्क रोड की शुरुआत होती है जो चीन को यूरोप, केंद्रीय एशिया, यूरेशिया, रूस से जोड़ता है वर्तमान में जब सी जिनपिंग सत्ता में आए तो 2013 में इस नीति की घोषणा की यह वर्तमान में बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के नाम से जाने जाती हैं जो सड़क रेल व समुंद्र मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व तक चीन की पहुंच को बनाने में मददगार साबित होगा मगर भारत के सामने इस परियोजना के कारण सबसे बड़ी चुनौती रणनीतिक है क्योंकि इस परियोजना के तहत चीन CPEC परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत यह भारत पीओके वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है जो भारत–पाक के बीच विवाद व क्षेत्र है और भारत का अधिकार क्षेत्र भी है साथ ही चमक चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा टीएनईसी चीन नेपाल गलियारा इन सब के माध्यम से चीन भारत के के पड़ोसी देशों के बहुत करीब आ रहा है और भारत अपने पड़ोसी से दूर जा रहा है जिसका रहा रणनीति खामियाजा भारत को भुगतना पढ़ रहा है

द्वितीय –कर्ज जाल (Debt trap) – इस शब्द को विदेशी संबंधों के जानकार ब्रह्म चेलानी द्वारा गढ़ा गया जिसके तहत चीन विभिन्न और छोटे देशों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराता है और इतना ऋण दे देता है जो उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है हावर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि चीन द्वारा डेढ़ सौ देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ऋण दिया जा चुका है ऐसे ही ऋण चीन द्वारा श्रीलंका को उसके हंबनटोटा बंदरगाह के विकास हेतु नेपाल में नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टीडाइमेंशनल कनेक्टिविटी सिस्टम हेतु दिया गया इसके अलावा चीन तकनीकी संस्थानों बांध निर्माण आदि में निवेश कर रहा है जिसके परिणाम स्वरुप यह देश भारत से दूर जा रहे हैं हाल ही में नेपाल द्वारा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को को अपना क्षेत्र बताना साथ ही श्रीलंका द्वारा समय–समय पर भारत का विरोध करना इन सब का कारण इन देशों में चीन द्वारा निवेश और चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है

तृतीय– मोतियों की माला (string of pearls) नीति चीन इस नीति के जरिए भारत को हिंद महासागर में तथा भारत को 360 डिग्री घेरना चाहता है इसलिए चीन हिंद महासागर के देशों के साथ सैन्य और आर्थिक ठिकानो का बना रहा है चीन अफ्रीका के पूर्वी भाग में जिबूती, ओमान में दुकम (Duqm port), ईरान चीन के बीच समझौता जिसके तहत चीन 25 सालों में 400 बिलियन +का निवेश करेगा साथ ही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन द्वारा 40 साल तक किराए पर ले लिया गया मालदीप के Feydhoo finolhu, Kunaaveshi, Maldives Capital, Hulhumale, प्रमुख है जिस पर चीन निवेश कर रहा है श्रीलंका में हंबनटोटा को 99 साल के लिए किराए पर ले लिया गया चीन द्वारा बांग्लादेश मे 2017 के समझौते के तहत गैस पाइपलाइन और मंगोला और चिटगॉन्ग (Chitagong) पोर्ट का एक्सेस दे दिया गया फिर म्यांमार का कोको द्वीप में एक छोटा सैन्य बेस बना रहा है जो मलक्का जलसंधि के नजदीक है इसके साथ ही नेपाल में चीन द्वारा तिब्बत के लहासा से काठमांडू से लुंबिनी तक एक रेल लाइन का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है जो भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक तक चीन की पहुंच को बना देगा इसके साथ ही चीन भारत को 360 डिग्री तक घेरने का प्रयास कर रहा है

चतुर्थ– व्यापारिक असंतुलन भारत की चिंता चीन को लेकर व्यापारिक घाटे की भी है व्यापारी के संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार में आयात ज्यादा होता है जबकि निर्यात कम होता है वर्तमान में भारत और चीन के बीच 2022 में 135. 98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ जिसमें भारत का व्यापारिक घाटा 100 अरब $ से भी ज्यादा पहुंच गया सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2015 से 21 के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार वृद्धि 75% तक बढ़ी है जो भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है

पंचम – चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों का सैन्य करण चीन के कुल हथियार निर्यात का 60% भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और म्यांमार को जाता है हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन देना श्रीलंका को P – 625 फ्रिग्रेटे जो युद्धपोत है वह दिए गए यह तेज गति से दिशा बदलने की दृष्टि

से निर्मित किया जाता है और जो अन्य नौकाओं के साथ चल चलकर उनकी रक्षा करते हैं श्री लंका को दिया गया बांग्लादेश को 2008 से 18 के बीच लगभग 1. 93 बिलियन डॉलर की हथियार चीन द्वारा दिए गए बांग्लादेश अपने कुल हथियार आयात का 72% चीन से खरीदता है म्यांमार मार्च 2013 के बाद से लगभग 720 मिलियन के हथियार चीन से खरीद चुका है जो चीन का सबसे बड़ा तीसरा आयातक देश है

छटा – सलामी सलासिंग (salami & slicing) नीतिः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टालिन के समय मत्यास स्वरोस्की (Matyas Rakosi) द्वारा किया गया भारत चीन के संदर्भ में इसका प्रयोग भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत द्वारा किया गया था इस नीति के तहत चीन पहले किसी क्षेत्र पर दावा करता है फिर उसे विवादित बनाता है उसके बाद उस पर छिटपुट हमले द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है यह हमले इतने छुटपुट होते हैं कि इनका अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा ध्यान आकर्षित भी नहीं किया जाता और वह देश जिस पर यह छिटपुट हमले हो रहे हैं उसे यह समझ नहीं आता कि इसका जवाब कैसे दिया जाए इसका उदाहरण 2017 का डोकलाम संकट 2020 का गलवान संकट और 2022 का तवांग वाले क्षेत्र पर चीन द्वारा छिटपुट झड़पें हैं जिसमें चीन ने इस पूर्ण युद्ध ना करके छोटे परंपरागत हथियारों जैसे डंडे और तार लगे छड़ी से लड़ाई की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस पर ध्यान भी आकर्षित नहीं किया गया भारत के लिए वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है चीन द्वारा इस प्रकार इस क्षेत्र को विवादित बनाना जिससे विदेशी निवेश या अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उस क्षेत्र पर निवेश भी नहीं किया जाता

भारत द्वारा चीन का प्रतिरोध करने हेतु अपनाई जा रही रणनीति

वर्तमान भारतीय सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है जो किसी भी फैसले को लेने में सक्षम है जो भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति के बाद 30 वर्षों में देखा गया इसी सरकार की इस स्थिति के कारण सी राजा मोहन ने मोदी कार्यकाल को थर्ड रिपब्लिक तक कह दिया वर्तमान सरकार अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती है चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के चीन को लेकर वर्तमान सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए गए प्राचीन को प्रति संतुलित और चीन की कार्यवाही का प्रत्युत्तर दिया जा सके

प्रथम– डायमंड नेकलस नीतिः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2011 में भारत के पूर्व विदेश सचिव ललित मानसिंह द्वारा किया गया यह एक अनौपचारिक नीति है जिसके तहत भारत चीन की मोतियों की माला की नीति के प्रत्युत्तर में देखा जा रहा है सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में भारत की भूमि अंडमान निकोबार जो चीन के लिए मलक्का दुविधा का काम करता है क्योंकि भारत ने 2019 में यहां के 3 दीपों आई एन एस खोसा (INS KHOASA) आई एन एस उत्कर्ष (INS Utkarsh) जो पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है तथा आई एन एस बाज जो कैंपबेल खड़ी में है तीनों को नेवल बेस के रूप में तब्दील किया साथ ही यहां 163 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया सबांग पोर्ट (Sabang Port) जहां भारत डीप सी पोर्ट का निर्माण कर रहा है 2018 में भारत ने यहां सैन्य अभ्यास किया जहां भारत के दो नौसेना जहाज आई एन एस सुमित्रा और आई एन एस वजीर यहां पर पहुंचे थे इसके बाद यहां से 1090 किलोमीटर दूर सिंगापुर का चेंगी नेवल बेस है जो 2017 में भारत सिंगापुर समझौते के तहत भारत के नौसेना जहाज को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करता है इसके बाद फिलीपींस भारत ने 2021 में द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास दक्षिणी चीन सागर में किया फिलीपींस ने जनवरी 2022 में 345 मिलियन डॉलर का समझौता किया जिसके तहत फिलिपिंस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा वियतनाम ने 2016 में कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किए और वियतनाम भारत से आकाश मिसाइल ध्रुव हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई दोनों देश Passex नाम से नौसेना युद्ध अभ्यास भी करते हैं जापान चीन की विस्तार वादी और आक्रामकता को रोकने हेतु सबसे प्रमुख भागीदार है मार्च 2021 में जापान द्वारा अंडमान निकोबार के विकास हेतु 4 बिलियन येन का ऑफर दिया यह ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत दिया गया है साथ ही दोनों देश चीन के वन बेल्ट वन रोड को रोकने हेतु 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इसके बाद मंगोलिया में जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने मंगोलिया की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान दोनों देश रणनीतिक भागीदारी भी बने इस यात्रा के दौरान भारत ने मंगोलिया को एक बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जिसके तहत भारत ने मंगोलिया के दक्षिण मे पहला तेल शोधन कारखाना डोर्नोगोवि प्रान्त मे लगाया गया साथ ही एक वायु गलियारा भी स्थापित किया जाएगा दोनों देशों के बीच नोमेडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट के तहत सैन्य अभ्यास भी होता है इसके बाद ईरान का चाबहार पोर्ट जो केंद्रीय एशिया में भारत की पहुंच को बनाएगा मगर यूएसए और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण भारत का यह समझौता यह भारत यह परियोजना थोड़ी विलंब हो रहा है इसके बाद ओमान का दुकम पोर्ट पर भी भारत की मौजूदगी है जो तीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट और जिबूती दोनों के बीचो बीच स्थित है 2018 से भारत यहां सैन्य अभ्यास भी कर रहा है इसके बाद सेशेल्स का आजमसन दीप (Assumption) में 2015 में पायरेसी और ट्रैफिकिंग को रोकने हेतु सेशेल्स के साथ कोस्ट गार्ड समझौता के लिए समझौता हुआ मगर 2018 से सेशल्स की आंतरिक नीति के कारण इतना समर्थ नहीं हो पाया इस नीति का अंतिम डायमंड मॉरीशस का अगेलेगा दीप है जहां आधारभूत संरचना का विकास सैन्य दृष्टिकोण से भारत द्वारा किया जा रहा है

द्वितीय – क्वाड और चीन प्रतिरोधः 2007 में जापान द्वारा प्रस्तावित मगर 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया इसमें ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए और भारत शामिल है जिस का उद्देश्य आर्थिक और रक्षात्मक दोनों ही है वैसे इसका मुख्य उद्देश्य साउथ चाइना सी जिस पर चीन दावा करता है और अपने अधिकार क्षेत्र को फैलाने का प्रयास कर रहा है यह सभी देश हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रयास को रोकना चाहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत में समूह का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह चीन को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है भारत को चीन द्वारा समय–समय पर वार्ड में शामिल होने के कारण धमकी भी दी जाती है और साथ ही चीन क्वाड को एशियन नाटो तक भी कहता है यह चारों देश मालाबार क्षेत्र मे नौ सैन्य अभ्यास भी करते हैं इसके माध्यम से व शक्ति प्रदर्शन करते हैं इन सब का उद्देश्य चीन को रोकना है और भारत भी इस ग्रुप में बिना चीन की परवाह किए शामिल है

तृतीयः RCEP (REGIONAL ECONOMIC COORPORATION PARTNERSHIP) यह समझौता आसियान के 10 देशों और अन्य देशों जिसे आसियान + 6 कहा जाता है जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया और चीन न्यूजीलैंड भी आते हैं के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जिससे भारत ने अपने को दूर किया क्योंकि इससे चीन का बहुत सा सामान समान भारत आ जाता जिसको भारत आयात नहीं करना चाहता था वह भी भारत आ जाता और भारतीय घरेलू उद्योग को भारी नुकसान पहुंच सकता था इसके लिए भारत ने

चीन के समान को रोकने हेतु रूल फॉर आरीजन की बात कही जिसके तहत भारत को कोई भी देश भारत में जो समान निर्यात करता था उसे बताना होता था कि उसका उत्पादन किस देश में होता है क्योंकि चीन बहुत से उत्पादकों को दूसरे देशों के माध्यम से भारत में भिजवा देता था जिस पर चीन को एतराज था और वह भारत की इस नीति को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं था इसके लिए भारत ने इसमें शामिल ना होकर चीन का सपना पूरा नहीं होने दिया और इस नीति को भी चीन को का प्रतिरोध करने की नीति के तहत देखा जा रहा है

चतुर्थ – अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियाराः यह माल परिवहन के लिए जहाज रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टीमॉडल नेटवर्क है 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में तय किया गया जिसमें बाद में 11 अन्य माध्य एशियाई देशों को भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया जिसमें अज़रबैजान आर्मेनिया क्पाकिस्तान तुर्की यूक्रेन जैसे देश शामिल है जिनके द्वारा भारत यूरेशिया मध्य एशिया और केंद्रीय एशिया तक पहुंच को बनाता है यह मार्ग भारत और रूस के बीच माल ढोने की लागत को 30: कम कर ता है और 40 दिनों का समय बचा लेता है 2014 में इसमें 2 मार्गों पर dry-run किया गया था पहला बंदर अब्बास के जरिए मुंबई से बाकू तक दूसरा बंदर अब्बास तेहरान और बंदर अंजली के रास्ते मुंबई से अश्न खान तक 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तीन दिवसीय मैरिटाइम इंडिया सम्मिट 2021 में आईएनएसडीसी में चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान व उज्बेकिस्तान को शामिल करने की बात इसमें कि भारत इस मार्ग के जरिए ठत् के विकल्प के रूप में भी पेश कर सकता है साथ ही उन देशों को भी एक विकल्प देगा चीन की नीति का हिस्सा है

निष्कर्ष

"वर्तमान समय अमेरिका के साथ गहरी बातचीत करने का, चीन का प्रबंध करने का, यूरोप से नए रिश्ते विकसित करने का, रूस को आश्वस्त करने का, जापान के साथ मिलकर यह सब कार्य करने का समय है "जयशंकर द्वारा दिया गया यह कथन उनकी पुस्तक "The India Way: Strategies for an Uncertain World" वर्णित है जिससे स्पष्ट होता है कि आज भारत पूरे विश्व के साथ संग्लन होने का प्रयास कर रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि आज भारत की विदेश नीति में बदलाव तो अवश्य आया है इसलिए भारत आज दो विपरीत विचारधाराओं वाले देशों जैसे रूस और अमेरिका दोनों से बातचीत कर रहा है उनका रणनीतिक भागीदार भी है और साथ ही साथ चीन जैसे पड़ोसी देश से आंखों में आंखें डाल कर बातचीत भी कर रहा है जिसने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि बीते दशक में भारत की विदेश नीति में बदलाव तो अवश्य आए हैं मगर साथ ही भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे चीन के साथ होने वाले व्यापार में असंतुलन भारत द्वारा वर्तमान समय में चीन का सामना करने व अन्य दुश्मनों का सामना करने के लिए उसका बढ़ता हुआ रक्षा बजट और रक्षा उपकरणों का बढ़ता हुआ आयात जिस पर भारत का बहुत पैसा खर्च हो रहा है जो कुल बजट का 2023–24 मे 14.3% है जिस कारण कल्याणकारी कार्यों जो भारत की घरेलू जरूरत है उसमें कमी आ सकती है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो भारत को चाहिए कि वह संतुलन की भूमिका निभाई और वर्तमान में घरेलू उत्पादन शक्ति को बढ़ाएं ताकि विदेशी मुद्रा कहा ना हो और भारत के लोगों को रोजगार भी मिल सके

संदर्भ सूची

1. (Nov–20–2017),, चाइनीस फॉरेन पॉलिसी विद शी जिनपिंग कैरेक्टरिस्टिक, सीताओ (XIETAO), कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल
2. (May–16–2015), मोदी रिचेस मंगोलिया इन फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन पीएम , हिंदुस्तान टाइम्स
3. (Nov–29–2022), एक्सपोर्ट्स आफ डिफेंस आइटम्स, टेक्नोलॉजी टू रिच आर. एस.17,000 करोड़ इन 2023, दा इकोनामिक टाइम्स
4. कोंडापल्ली, एस., शी जिनपिंग एंड द रिसरेक्शन ऑफ़ द मिडल किंगडम, 12/02/2018, द एशियन डायलॉग
5. (Nov–15–2022), तेज़ हवाएँ, अस्थिर पानी, यहाँ तक कि खतरनाक तूफान भीरू शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी विदेश नीति को समझना, द वायर
6. (23–Dec.2014), सी डिस्मेंटल दा "न्यू गैंग ऑफ़ फोर' ञविद प्रोब ऑफ़ Hu's ऐड, ब्लूम्स बर्ग
7. बक्केवाल्ड , जे.एल., व्हाट शीज़ (XI'S) फर्स्ट डिकेड टेल अस अबाउट दा नेक्स्ट, 13/oct/2022, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन
8. (Jun–14–2020), इन चाइना कॉलोनाइजिंग इंडियास नेबर्स विद आर्म्स डील्स एंड हेफ्टी डील्स?, वियन न्यूज़
9. (Sep–1–2020),सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स क्या है? , द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया
10. (June–06–2022), ईस चाइना हिटिंग बैक अट इंडिया आईएनएसडीसी प्लान?,दा डिप्लोमेट
11. (2014, June 16),इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इन भूटान टू चेक चाइना इनफ्लुएंस, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट
12. अहलावत, डी. और हूजेस,अल. (2018) इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन डोकलाम रूअलिगनिंग (Aligning) रियलिज्म वेद नेशनल कैरेक्टर स्टिक्स, राउंड टेबल
13. यादव, आर. एस.(2021), इंडियन फॉरेन पॉलिसी पोस्ट कोल्ड वॉर इयर्स, पीयरसन पब्लिकेशन
14. मख़र्जी, पारममता, देब, के. अ., पाांग, ममआओ, (2016), चीन और भारतरू इतिहास, संस्कृति, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, सेज़ भाषा पब्लिकेशन
15. मोहन, सी, आर. (2015), मोदी इज वर्ल्डः एक्सपेंडिंग इंडियाज स्फीयर ऑफ इनफ्लुएंस, हार्परकोलिंस पब्लिकेशन भारत
16. हॉल, आई (2019) मोदी एंड री इन्वेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी प्रेस
17. चोलिया, एस., (2016), मोदी डॉक्ट्रिन रूद फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ब्लूम्सबर्ग पब्लिकेशन
18. पंत, एच.वी., (2019) इंडियन फॉरेन पॉलिसीरू मोदी अरा, हर आनंद पब्लिकेशन
19. रल्हाम,ओ.पी. और गुप्ता एस.आर. (2017), फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदीरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वरूप बुक पब्लिकेशन
20. मेनन, एस. (2016) चोइसस इनसाइड मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया
21. जयशंकर,एस., (2020), इंडिया वे रू स्ट्रैटेजिस आफ अनसर्टेन वर्ल्ड, हार्पर कोलिंस इंडिया
22. गोखले, वी., (2022) स्ट्रैटेजिक चौलेंजिस इन इंडिया 2030 हार्परकोलिंस इंडिया
23. पांडे, ए. (2020) फ्रॉम चाणक्य टू मोदीरू इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हार्परकोलिंस पब्लिकेशंस